26 मई, 2015

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

मुद्दा सार

प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरा

डॉ. स्तुति बनर्जी*

"नया उत्साह: नए कदम" वह शीर्षक है जो भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध के नए स्तर को परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक द्विपक्षीय कनाडा दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर ने उनकी मेजबानी की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 42 वर्षों में ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर (14 - 16 अप्रैल, 2015) की पहली यात्रा थी। इस दौरे में कनाडा के राजनैतिक, व्यापारिक और शैक्षिक नेताओं के साथ व्यापक मेल-जोल हुआ और भारतीय जनसमुदाय (डायस्पोरा) के साथ ठोस विचार-विनिमय किया गया। कनाडा के लिए इस दौरे का महत्व इस तथ्य से आंका जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीन शहरों के दौरे में प्रधानमंत्री हार्पर उनके साथ गए।

इस दौरे में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन तथा परस्पर हित के व्यापक क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पूर्ण विस्तार के साथ आदान-प्रदान की संभावनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। यह कुछ समय से ठप पड़े संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम था। यह एक मुद्दा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी उठाया गया जब उन्होंने कहा कि 'अतीत के रिश्तों में ठहराव आ गया था।'[1]

इस यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में "द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता को नवजीवन प्रदान करने के महत्व" पर जोर दिया गया और द्विपक्षीय संबंधों में जारी विविधता, विकास तथा घनिष्ठता का स्वागत किया गया जो लोकतंत्र, बहुलवाद, सहनशीलता, मानवाधिकारों और कानून के शासन के साझा मूल्यों में समाहित है और आर्थिक संपर्क का विस्तार करने एवं लोगों के दीर्घकालिक आपसी संबंधों पर आधारित है। दोनों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के दौरान अतिरिक्त समय में बातचीत करने के अलावा

नियमित विचार–विमर्श करने पर भी सहमत हुए।[2]

भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करके द्विपक्षीय संबंध के लिए एक 'मार्ग' तय करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है जिसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ भारत के विकास के लिए व्यापार तथा प्रौद्योगिकी आकर्षित करना, स्मार्ट शहर तथा कृषि उद्योग और अनुसंधान एवं शिक्षा शामिल है। आशा है कि यह दौरा भारत और कनाडा के बीच के संबंध को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगा।

परमाणु ऊर्जा सहयोग

ऊर्जा उस संबंध का एक प्रमुख पहलू है जो भारत कनाडा के साथ विकसित करना चाहता है और परमाणु ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है, जहां दोनों राष्ट्रों ने अतीत में सहयोग किया है। वर्ष 1955 में, कनाडा की सरकार ने यह घोषणा की कि वह कोलम्बो योजना के तत्वाधान में भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी का अंतरण करेगी। अप्रैल 1956 में प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री रेड ने औपचारिक रूप से कनाडा-भारत (सीआईआर) करार पर हस्ताक्षर किए और कनाडा सरकार ने वर्ष 1963 में भारत को प्रथम *कान्डु* (CANDU) रियेक्टर बेचे। हालांकि परमाणु परीक्षणों को करने के भारत के निर्णय और परमाणु अप्रसार संधि (एनटीपी) तथा परमाणु नि:शस्त्रीकरण तथा अप्रसार पर ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय करारों के संबंध में भारत के पृथक दृष्टिकोण के कारण संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

इतना होने पर भी कनाडा द्वारा भारत-अमरीका असैन्य परमाणु करार को दिये गए समर्थन को दोनों राष्ट्रों के बीच एक नए 'ऊर्जामय' संबंधों की शुरूआत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति करने के संबंध में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के कामेको के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये जाने का स्वागत किया। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। इस आपूर्ति अनुबंध/संविदा को कनाडा–भारत परमाणु सहयोग करार (एनसीए), जो सितंबर, 2013 में लागू हुआ, के तहत संभव बनाया गया। 572,000 टन यू308 (485000टीयू) के ज्ञात यूरेनियम संसाधनों के साथ-साथ सतत अन्वेषण के साथ ही, भविष्य में वैश्विक मांगों[3] को पूरा करने में कनाडा को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है और भारत में कनाडा का विकसित होता बाज़ार है। दोनों देशों ने माना है कि यह करार भारत-कनाडा असैन्य परमाणु सहयोग को एक नया महत्व प्रदान करेगा।

दोनों नेताओं ने परमाणु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के महत्व को समझते हुए अपने-अपने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों तथा अनुसंधान संस्थाओं को प्रोत्साहित किया है कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में दीर्घकालिक तथा परस्पर लाभप्रद अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए तंत्र स्थापित करें और समाज को लाभान्वित करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स के अनुप्रयोग में परस्पर लाभप्रद सहभागिताओं की तलाश करने की आवश्यकता को समझें।

कनाडा परमाणु अनुसंधान एवं विकास में विश्व में अग्रणी रहा है और यह चिकित्सा निदान/जांच एवं कैंसर के उपचार सहित, शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्यातक है। सकल घरेलू उत्पाद, सरकारी राजस्व तथा रोजगार के मामले में कनाडियाई परमाणु उद्योग कनाडा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसी 150 से अधिक कम्पनियां हैं, जो कनाडा परमाणु ऊर्जा लिमिटेड (एइसीएल) तथा यूटिलिटी/उपयोगिताओं को उत्पादों और/अथवा सेवाओं की आपूर्ति करती हैं। यह उद्योग मुख्य रूप से ओंटारियो में केन्द्रित है और कुछ हद तक सासकार्टचवान, क्यूबेक और न्यू ब्रंसविक में अवस्थित है। अर्थव्यवस्था तथा समाज के प्रति कनाडियाई परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का योगदान ऊर्जा लाभों से बढ़कर है। इसके परिणामस्वरूप, एक उद्योग स्थापित हुआ है, जो प्रतिवर्ष लगभग 6.6 अरब डॉलर का राजस्व सृजित करता है (इसमें उत्पादित परमाणु विद्युत का मूल्य भी शामिल है, जो प्रतिवर्ष लगभग 5 अरब डॉलर निर्यात बिक्री – कांडू (CANDU) उपकरण/सेवा निर्यात (50 करोड़ डालर), यूरेनियम (50 करोड़ डालर), चिकित्सा तथा औद्योगिक आइसोटोप्स तथा संबद्ध उपकरण (30 करोड़ डॉलर) - शामिल है) को दर्शाता है। इन आंकडों में परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लाभों तथा 1.5 अरब डॉलर के करों के माध्यम से संघीय तथा प्रांतीय राजस्वों को शामिल नहीं किया गया है। बिलकुल हाल के आंकड़ों से संकेत मिला है कि कनाडा में परमाणु उद्योग से संबंधित वार्षिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) 30,000 से अधिक है। लगभग 21 हज़ार प्रत्यक्ष रोजगार, 10 हज़ार अप्रत्यक्ष रोजगार (इस उद्योग के ठेकेदार) के साथ-साथ 40 हज़ार उपोत्पाद (स्पिन-ऑफ) रोजगार हैं।[4]

विश्व परमाणु संगठन (डब्ल्यूएनए) के अनुसार, परमाणु ऊर्जा उत्पादन/सृजन में सब से अधिक विकास की संभावना एशिया, विशेषकर भारत, चीन और दक्षिण एशिया में है। भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ इस मांग का बढ़ना जारी रहेगा। इस उभरती अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए भारत परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र में सभी विकल्पों की तलाश कर रहा है। भारत ने एक स्वदेशी असैन्य परमाणु आधार/बेस विकसित किया है, लेकिन यह वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में है और भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की तलाश में है जो इसमें सहायता कर

सकें। भारत का उद्देश्य भविष्य में परमाणु प्रौद्योगिकी के निर्यात में भूमिका अदा करने का है।

उपरोक्त को देखते हुए यह कनाडा के हित में है कि वह भारत के साथ एक असैन्य परमाणु सहयोग करार को आगे बढ़ाए। इससे कनाडा को भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी बेचने की अनुमति मिल जाएगी। इससे दोनों राष्ट्रों को लाभ होगा; आर्थिक रूप से, यह कनाडा के लिए व्यवहार्य होगा जबकि भारत, कांडु (CANDU) रिएक्टरों के अपने अतीत के अनुभव के साथ, इस संबंध का विस्तार करने का इच्छुक होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास ने राष्ट्रों को भारत के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है। आज विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमरीका और जापान भारत के साथ सक्रिय संपर्क कर रही हैं। ऐसे में, भारत में (हो रहे) विकासों की अनदेखी करना कनाडा के हित में नहीं होगा। इसी प्रकार, भारत, जिसकी अभिलाषा एक बड़ी ताक़त बनने की है, पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यदि इसने कनाडा से व्यापार/संपर्क नहीं किया।

इस सहयोग को आगे ले जाने हेतु, दोनों देशों ने परस्पर लाभ के लिए प्रेसराइज्ड हेवीवाटर रियेक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने-अपने उद्योगों की संबद्ध ताकतों का लाभ उठाने के साथ-साथ वैश्विक परमाणु ऊर्जा आवश्यकताओं के लाभ के लिए भी एक सहयोगी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। इन्होंने अपनी कम्पनियों के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को भी प्रोत्साहित किया और कनाडा ने ऐसे सहयोग को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में विदेशी कम्पनियों की संभावित भागीदारी के साथ *इंडिया न्यूक्लियर इनश्योरेंस पुल* की स्थापना करने का स्वागत किया है, ऐसा संयुक्त वक्तव्य में कहा गया। दोनों राष्ट्र सुरक्षा तथा विनियामक मुद्दों पर अनुभवों तथा विकासों को साझा करने पर सहमत हुए हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए, परमाणु तथा विकिरण सुरक्षा विनियमन के क्षेत्र में विनियामक सहयोग के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और कनाडियाई परमाणु सुरक्षा आयोग ने एक करार को अंतिम रूप दिया है। दोनों देश परस्पर लाभ के लिए प्रेशराईज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में अपने उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाने के साथ-साथ वैश्विक परमाणु ऊर्जा आवश्यकताओं के लाभ के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। कनाडा ने अक्तूबर 2015 में भारत के लिए योजनाबद्ध कनाडियाई असैन्य परमाणु व्यापार मिशन की बात दोहराई है।[5] ये करार 'परस्पर भरोसे और विश्वास के नए स्तर को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा की शक्ति के साथ अपने विकास को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों में इससे सहायता मिलेगी।"[6]

'ऊर्जा' संबंध परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है; भारत ओएनजीसी विदेश, जो कनाडा में परियोजनाओं में निवेश करने की योजना बना रहा है, जैसी भारतीय तेल कम्पनियों के साथ कनाडा में विशाल प्राकृतिक गैस तथा तेल भंडारों के क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश भी कर रहा है।

अर्थव्यवस्था

भारत अपने आर्थिक परिवर्तनों/सुधारों में सहयोग के लिए कनाडा की ओर देख रहा है। दोनों राष्ट्रों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार संबंध अभी पूर्ण क्षमतावान नहीं बन पाए हैं। दोनों देशों के बीच अतीत के अच्छे संबंधों और इनकी संस्थाओं के बीच अनेक समानताओं के होते हुए भी व्यापार तथा निवेश उपेक्षित रहा है। दोनों प्रधानमंत्री सहमत हुए कि द्विपक्षीय विदेशी निवेश संवर्धन तथा सुरक्षा करार (बीआईपीपीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने से दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश सहयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक सुविधा होगी। कनाडा ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए विभिन्न पहलों में रूचि दिखाई है, जिसमें 'स्मार्ट सिटी' पहल, वर्ष 2022 तक सभी के लिए वहनीय आवास और सबसे महत्वपूर्ण 'मेक इन इंडिया' पहल शामिल है। इससे दोनों राष्ट्रों को सहयोगी उपक्रमों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे भरोसेमंद आर्थिक संबंध विकसित हो सकेंगे।

कनाडा ने अपनी वैश्विक बाजार कार्ययोजना में भारत को प्राथमिकता दी है। अपनी योजना के माध्यम से कनाडा सरकार उन बाज़ारों में अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करेगी, जो कनाडियाई व्यापार के लिए सर्वाधिक वायदे करेंगे। यह कनाडा सरकार की "आर्थिक कूटनीति" की संकल्पना का विस्तार भी है। भारत की पहचान उन प्रमुख अवसरों के लिए की गई है, जो यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि संधारणीय प्रौद्यौगिकी तथा रेलवे जैसे अनेक अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराता है। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच रेल, नागर विमानन और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर (हस्ताक्षर) हुए।

भारत यह भी प्रत्याशा कर रहा है कि इसकी उन्नत स्थिति का परिणाम कनाडा द्वारा भारत में अधिक निवेश किए जाने के रूप में निकलेगा। वर्ष 2013 में, कनाडा में 3 अरब 77 करोड़ 60 लाख रूपए के भारतीय निवेशों की तुलना में कनाडा का (भारत में) निवेश अपेक्षाकृत कम, अर्थात 61 करोड़ 30 लाख रूपए था।[7]

भारत-कनाडा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र नीति वार्ता, जिसकी घोषणा वर्ष 2013 में हुई थी, एक ऐसा मंच है, जिसके जरिए भारत और कनाडा अपने वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर संबंध विकसित करके उन्हें कायम

रख पाएंगे और भारतीय तथा कनाडियाई वित्तीय संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकेंगे। कनाडा-भारत ईएफएसपी वार्ता का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना और दोनों देशों के वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के बीच घनिष्ठ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना है। एक दूसरे के वित्तीय क्षेत्र की रूपरेखा की बेहतर समझ विकसित करके, वित्तीय क्षेत्र के नियामक परस्पर हित के नीतिगत तथा विनियामक मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर सकते हैं। ईएफएसपी वार्ता प्रक्रिया सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत और कनाडा की संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है जब दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश संबंध विकसित हो रहे हैं।[8]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि वर्ष 2016 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद को पीछे छोड़ देगा और भारत विश्व की सबसे तेज विकसित होने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के वैश्विक सहयोगियों को प्रधानमंत्री मोदी के इस आश्वासन की कनाडा में अत्यधिक सराहना की गई है कि सरकार अफसरशाही प्रक्रिया को कम करने तथा निवेशों को आकर्षित करने के लिए कर संबंधी कानूनों को आसान बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। 'मेक इन इंडिया' पहल, जिसका उद्देश्य भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करना है, कनाडा को भारत का सहयोगी बनाने का उपयुक्त अवसर उपलब्ध करा रहा है। भारत में विशाल फर्मों द्वारा विनिर्माण एककों की स्थापना करने से भारत की युवा जनता, जो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है, को रोजगार उपलब्ध होगा जबकि उद्योग के लिए, यह कदम उन्हें सस्ते मजदूर तथा कार्य करने हेतु एक स्थिर आर्थिक वातावरण प्रदान करेगा।

शिक्षा तथा कौशल विकास

भारत की विशाल युवा जनसंख्या केवल रोजगार के अवसर मात्र की ही तलाश नहीं कर रही है, बल्कि वह उच्च जीवन स्तर की इच्छा से बेहतर शिक्षा भी चाहती है। कनाडा के विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा को द्विपक्षीय संपर्क के लिए प्राथमिकताओं के प्रमुख क्षेत्रों में से एक माना है और अधिकाधिक छात्रों, शिक्षकों तथा लोगों के आपसी संपर्कों पर ध्यान देने पर सहमति जताई है। भारत तथा कनाडा दोनों ने पुष्टि की है कि शिक्षा में सहयोग को दोनों देशों में मानव संसाधनों के स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने गौर किया कि कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यनीति के तहत भारत प्राथमिकता वाला देश है।

भारतीय छात्र अधिकाधिक संख्या में अपने शैक्षिक अनुभव तथा अर्हताओं को बढ़ाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर देख रहे हैं जबकि कनाडा के उच्चतर शिक्षा के विश्वविद्यालय तथा संस्थान अधिक

अंतर्राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। भारत की अत्यधिक शैक्षिक आवश्यकता बड़े पैमाने पर देश की अक्षमता पर आधारित है, जहां नई भारतीय अर्थव्यवस्था में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक श्रमिक बल तैयार करने और विशाल तथा उभरती छात्र जनसंख्या के लिए संगत तथा स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकारी संसाधन सीमित संख्या में हैं।[9] इस प्रकार, छात्रों की भर्ती के साथ-साथ भागीदारी तैयार करने, संबद्धता, संयुक्त प्रोग्रामिंग तथा शिक्षकों एवं विद्वानों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में कनाडियाई संस्थाओं और उनके भारतीय समकक्षों के बीच निकट संपर्क, बेहतर अर्हताप्राप्त तथा ज्ञानी वैश्विक नागरिकों के निर्माण हेतु इस परस्पर रूचि को विकसित करने की दिशा में एकदम सही कदम होगा।

शैक्षिक सहयोग भारत और कनाडा के बीच लाभप्रद संबंध विकसित करने में सहायक होंगे। इससे न केवल एक ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी, बल्कि यह भारत को अपने नागरिकों को कौशल विकास संबंधी ज्ञान प्रदान करने के इसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। इस संबंध में, भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और 13 कनाडियाई कॉलेजों, संस्थानों और क्षेत्र कौशल परिषदों के बीच कृषि, परिधान एवं वस्त्र, मोटर वाहन, विमानन, निर्माण, हरित अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य परिचर्या, हाइड्रोकार्बन, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और *इलेक्ट्रॉनिक्स* एवं जल के क्षेत्र में (हस्ताक्षरित) तेरह समझौता ज्ञापन सर्वाधिक स्वागत योग्य हैं।

इस संबंध में एक विकल्प, जिसकी तलाश की जा सकती है, भारत में अपतटीय परिसरों (offshore campuses) की स्थापना करना है। यह दोनों राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों के बीच संबंध विकसित करने के अतिरिक्त होगा। दोनों राष्ट्रों को शिक्षण के और अधिक केंद्रों की स्थापना करके और अपने-अपने देश में अनुसंधान कार्य कर रहे छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उदार छात्रवृत्तियां प्रदान करके उच्चतर शिक्षा की अपनी-अपनी संस्थाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है।

घरेलू स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के स्वदेशी शिक्षा क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी कनाडा की सहायता मांगी जा सकती है। इसमें स्कूलों की संख्या बढ़ाने तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुदेशों के स्तर में सुधार करने में भारत की सहायता करना शामिल है। एक अन्य विकल्प अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कनाडा और भारत के बीच शिक्षा संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए दीर्घकालिक अथवा लघुकालिक छात्र तथा शिक्षकों के आदान-प्रदान का महत्व और इस प्रक्रिया में कनाडियाई तथा भारतीयों दोनों के ही अनुभवों को समान रूप से समृद्ध करने से इंकार नहीं किया जा सकता और इसे जारी रखने तथा विकसित करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।[10] अधिकाधिक कनाडा-भारत केंद्रों की स्थापना करने से भी आपसी संबंधों में लाभ मिलेगा।

अरबों भारतीय प्रवासियों, जो कनाडा को अपना घर कहते हैं, के साथ दोनों देशों के समाज में बेहतर समझ को बढ़ावा देना और गहरे संबंध विकसित करना लाभप्रद होगा। हालांकि, अमरीका में अपने समकक्षों के विपरीत, कनाडा के भारतीय समुदाय ने भारत-कनाडियाई द्विपक्षीय संबंध को प्रोत्साहित करने में अब तक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण भारतीय समुदाय में अलग-अलग जनसांख्यिकीय विशेषताओं का होना है। अमरीका के विपरीत, कनाडा के भारतीय समुदाय में पंजाब के प्रवासियों की बहुलता है और खालिस्तान के मुद्दे पर मतभेद है। उस आन्दोलन में भारतीय समुदाय के कुछ लोगों की भूमिका ने प्रवासी भारतीय समुदाय और भारत के बीच मतभेद पैदा किए हैं। ऐसी आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस अंतर को पाटने और संबंधों में एक भूमिका निभाने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करने में समर्थ रहे हैं। यह भी आशा है कि बढ़ते गुजराती भारतीय समुदाय/डायस्पोरा की वित्तीय, व्यावसायिक तथा राजनैतिक सफलता कनाडा में भारत के लिए संतुलन कायम करने में समर्थ होगी।

कनाडा में प्रवासी भारतीय समुदाय/डायस्पोरा से अपील करना भारत की विकास प्रक्रिया में उन्हें प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपनी समस्याओं का समाधान तलाशने तथा विकास करने की क्षमता मौजूद है, लेकिन इसमें सहायता के लिए भागीदारों की ज़रूरत है। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय/डायस्पोरा का आह्वान किया कि वे भारत के भागीदार बनें। अब इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या प्रधानमंत्री की अपील वास्तविक परिणाम लाएगी। प्रवासी भारतीय समुदाय से अपील किया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उस देश के राजनैतिक परिदृश्य में सक्रिय हैं और भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह तथा अन्य परमाणु व्यापार तथा निर्यात व्यवस्था में शामिल होने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट के लिए भारत की बोली के लिए कनाडा के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। भारत केवल एफडीआई धन-प्रेषण तथा ज्ञान एवं उद्यम साधनों के हस्तान्तरण के जरिये ही प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को नहीं देख रहा है, बल्कि यह भारत में सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी तथा आईटीईएस क्षेत्रों के उत्थान में योगदान करके अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भी प्रवासी भारतीय समुदाय तक पहुंचना चाहता है। भारतीय पीढ़ी के लगभग एक अरब कनाडावासी एक महत्वपूर्ण आधार/नींव हैं, जिनपर लोगों के आपसी संपर्क को प्रोत्साहित किया जाना है। वे दोनों देशों के बीच सामुदायिक सेतु का निर्माण करते हैं, जो दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत बंधन को सुदृढ़ बनाएगा। भारतीय मूल के कनाडियाइयों के समुदाय द्विपक्षीय व्यवसायिक संबंधों के विनिमय तथा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार का कार्य करते हैं।

निष्कर्ष

1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत ने धीरे-धीरे स्वयं को एक उभरती ताकत के रूप में

बदल लिया है, जिसकी हाल की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का औसत आठ प्रतिशत है। लगातार वैश्विक बाज़ार के उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा कार्य किया है। तेज़ी से विकसित होते भारत, जो अब विश्व की सबसे तेज उभरती विशाल अर्थव्यवस्था है, को अपने विकास को शक्ति प्रदान करने तथा अपना विनिर्माण आधार तैयार करने के लिए कच्ची सामग्रियों, ऊर्जा और विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ेगी। कनाडा के पास देने के लिए ये चीजें प्रचुर मात्रा में हैं और इस प्रकार, कनाडा भारत के साथ दीर्घकाल से सुषुप्त पड़े अपने संबंध को पुन: क्यों नहीं विकसित नहीं करेगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। भारत के साथ कनाडा के संबंध सभी क्षेत्रों में हैं और लगभग प्रत्येक क्षेत्र सहयोग के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। लघुकालिक चुनौतियों के कारण वैसे दीर्घकालिक अवसर लुप्त नहीं होने चाहिए जो अनेक क्षेत्रों में तेज़ी से सामने आ रहे हैं।

***

**डॉ. स्तुति बनर्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*

समाप्ति नोट:

---

[1] ---, "ओटावा, कनाडा में कनाडा के प्रधानमंत्री, श्री स्टीफेन हार्पर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री का मीडिया के लिए वक्तव्य का पाठ", http://www.narendramodi.in/text-of-pms-media-statement-during-joint-press-interaction-with-pm-of-canada-mr-stephen-harper-at-ottawa-canada/, 10 अप्रैल, 2015 को एक्सेस किया गया।

[2]कनाडा सरकार, प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर, "भारत-कनाडा संयुक्त वक्तव्य", http://pm.gc.ca/eng/news/2015/04/15/india-canada-joint-statement.

[3] विश्व परमाणु संघ,"कनाडा में यूरेनियम", 17 दिसम्बर, 2014, http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Canada--Uranium/, 10 अप्रैल, 2015 को एक्सेस किया गया

[4] कनाडा सरकार, "कनाडाई परमाणु उद्योग और इसका आर्थिक योगदान", http://www.nrcan.gc.ca/energy/uranium-nuclear/7715, 17 दिसंबर, 2014 को एक्सेस किया गया

[5] कनाडा सरकार, प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर, "भारत-कनाडा संयुक्त वक्तव्य", http://pm.gc.ca/eng/news/2015/04/15/india-canada-joint-statement, 10 अप्रैल, 2015 को एक्सेस किया गया।

[6] विदेश मंत्रालय, "ओटावा, कनाडा में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री का मीडिया के लिए वक्तव्य", http://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2507, 10 अप्रैल 2014 को एक्सेस किया गया।

[7] कनाडा सरकार, विदेशी मामलों, व्यापार और विकास कनाडा, वैश्विक कार्य-योजना, "प्राथमिकता बाजार भारत", http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/markets-marches/india-inde.aspx?lang=eng, 10 अप्रैल 2015 को एक्सेस किया गया।

[8] ज़ी न्यूज, "कनाडा, भारत आर्थिक, वित्तीय सेक्टर नीति पर वार्ता जारी रखेंगे", http://zeenews.india.com/news/india/canada-india-to-continue-talks-on-economic-financial-sector-policy_1545429.html, 10 अप्रैल 2015 को एक्सेस किया गया।

9 विदेश मामले और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर स्थायी सीनेट समिति, सीनेट ऑफ कनाडा, " नई वैश्विक अर्थव्यव्स्था में कनाडा के लिए एक कार्ययोजना: रूस, भारत और चीन के उदय पर प्रतिक्रिया", http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/403/fore/rep/rep07jun10-e.pdf, 10 अप्रैल, 2015 को एक्सेस किया गया।

[10] पूर्वोक्त